

देश के सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फरि अव्वल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी नये आँकड़ों के अनुसार देश के सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फरि अव्वल रहा है।

प्रमुख बटि

- मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर मात्र 0.7 प्रतशित रही, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोज़गारी दर 7.1 प्रतशित थी। इससे पहले मार्च, अप्रैल 2022 में भी छत्तीसगढ़ की बेरोज़गारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतशित थी।
- सीएमआईई के नये आँकड़ों के मुताबकि देश के कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में मध्य प्रदेश 1.6 प्रतशित, गुजरात 2.1 प्रतशित, ओडिशा 2.6 प्रतशित, उत्तराखंड 2.9 प्रतशित, तमलिनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1 प्रतशित, महाराष्ट्र और मेघालय 4.1 प्रतशित, कर्नाटक 4.3 प्रतशित, आंध्र प्रदेश 4.4 प्रतशित, पुदुच्चेरी 5.6 प्रतशित, केरल 5.8 प्रतशित शामिल है।
- देश में सबसे अधिक बेरोज़गारी दर हरियाणा में 24.6 प्रतशित, राजस्थान में 22.2 प्रतशित, जम्मू और कश्मीर में 18.3 प्रतशित, त्रपुरा में 17.4 प्रतशित, दलिली में 13.6 प्रतशित, गोवा में 13.4 प्रतशित, बहिर में 13.3 प्रतशित, झारखंड में 13.1 प्रतशित, हमाचल प्रदेश में 9.6 प्रतशित, तेलंगाना में 9.4 प्रतशित, पंजाब में 9.2 प्रतशित, असम में 8.2 प्रतशित तथा सकििम में 7.5 प्रतशित दर्ज़ की गई।
- साढ़े तीन साल पहले छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर शासन का सर्वाधिक ज़ोर रहा।
- सरकार बनने के तुरंत बाद कसिनों को ऋण तथा लंबति सचिाई कर की माफी से इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद राजीव गाँधी कसिन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गाँव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गाँधी ग्रामीण भूमहीन कसिन न्याय योजना, नई औद्योगिकि नीति का नरिमाण, वन तथा कृषि उपजों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था, उपजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडशिन, ग्रामीण औद्योगिकि पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि तथा 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीद, तैदूपत्ता संग्रहण पारशिरमकि दर में वृद्धि, मछलीपालन तथा लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा, परंपरागत शलिपयिों, बुनकरों तथा उदयमयिों को प्रोत्साहन, हर ज़िले में सी-मार्ट की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए।